DS-SSS/6.00/4B

THE NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2017 (Contd.)

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : सर, यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए जो नाबार्ड का बिल पेश किया गया है, उसके विषय में मैं अपने विचार यहाँ रखने के लिए खड़ी हुई हूँ और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ सूचनाएँ शेयर करना चाहती हूँ।

सर, राष्ट्रीय कृषि और औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) बिल, जिस पर आज इस सभागृह में चर्चा हो रही है, उस नाबार्ड के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। यह एक ऐसी संस्था है, जिसको अगर हम भारतवर्ष की अर्थवाहिनी कहें, तो गलत नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will take one more hour and pass this Bill. I hope the House agrees.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will sit for one more hour and pass this Bill.

श्रीमती रजनी पाटिल : सर, इस देश के ग्रामीण लोग, किसान, हथकरघे पर काम करने वाले आर्टिज़न्स, इन सबके लिए एक जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिसको आधारभूत सुविधा कहते हैं, वह देने वाली यह एक संस्था है। सर, जब रूरल डेवलपमेंट की बात आती है, तो नाबार्ड ने पहले वॉटरशेड में काम किया था। मुझे याद है कि नाबार्ड ने पहली बार महाराष्ट्र में जर्मनी गवर्नमेंट के माध्यम से वॉटरशेड डेवलपमेंट का काम

शुरू किया था। जब लोग इरिगेशन और सिंचाई की बातें करते थे, तब नाबार्ड ने वॉटरशेड की बात की थी। सर, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में इरिगेटेड इलाका ज्यादा है और वहाँ सिर्फ इरिगेशन नहीं, बल्कि वॉटरशेड की बहुत आवश्यकता है, यह पहली बार नाबार्ड ने जान लिया था। जब लोग खेती की बात करते थे, तब नाबार्ड ने नॉन-फार्मिंग सेक्टर या रूरल मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम आज हम हिन्दुस्तान में देख रहे हैं।

सर, मुझे नाबार्ड के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह लगती है कि जब आरबीआई ने वर्ष 1992 में माइक्रो फाइनेंस शुरू किया, जब महिलाओं के लिए सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स शुरू किए, तो हमारी महिलाओं में एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा होने की शुरुआत हो गई थी। महिलाएँ जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती हैं, तब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि किसी भी महिला का सबलीकरण हुआ है। उसको लेकर इस देश में कम से कम लाखों बचत-घर, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं, तैयार हो गए हैं, जिनके माध्यम से महिलाएँ आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। जब तक महिलाओं को साथ नहीं लेंगे, उनकी इन्क्लूसिव ग्रोथ नहीं करेंगे, तब तक यह समाज आगे नहीं जा सकता है। एक बार महात्मा गाँधी ने कहा था कि जब तक हम महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनको साथ नहीं लेंगे, तब तक समाज में कोई भी बदलाव अधूरा रह जाएगा।

सर, मंत्री जी ने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है कि उसके शेयर का प्रतिशत, जो पहले 5,000 करोड़ रुपये था, उसको बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाना चाहिए और यह

आरबीआई के सहयोग से किया जाना है। मैं समझती हूँ कि यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। इसका कारण यह है कि इससे नाबार्ड की borrowing capacity में बढ़ोतरी हो जाएगी और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम होगा। लेकिन, उसमें हम कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं।

सर, नाबार्ड में थ्री-टीयर सिस्टम होता है। सर, महाराष्ट्र इन चंद सालों में अगर किसी चीज के लिए जाना जाता है, तो वह सिर्फ इसीलिए जाना जाता है कि महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्याएँ की जाती हैं। यह नाबार्ड ही एक संस्था है, जो किसानों को पैसे देकर उनकी सहायता करने का काम करती है। वह उनको डायरेक्ट पैसे नहीं देता, लेकिन उसका जो थ्री-टीयर सिस्टम है, उसके माध्यम से वह उनको पैसे देता है। किसानों तक वह पैसा राज्य बैंक, जिला बैंक और सोसायटीज़ के माध्यम से पहुँचता है, लेकिन इसमें अधिक स्पष्टता और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि आखिरी आदमी तक यह मदद अच्छी तरह से पहुँचे। सर, जिला में सहकारी बैंकों की स्थिति बहुत खराब है। बहुत-सी जगहों पर उनको बन्द करने के किस्से सुनाई देते हैं। उसके लिए भी नाबार्ड की ओर से आरबीआई के सहयोग से कुछ उपाय करने जरूरी हैं।

सर, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में शुगर फैक्टरीज़ का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। शुगर फैक्टरी का एक ऐसा बिजनेस है, जिसमें नाबार्ड के थ्रू महाराष्ट्र सहकारी जिला बैंक से री-फाइनेंस, री-इनवेस्टमेंट होता है। सर, यह सच है कि हमारे यहाँ कभी बाढ़ आती है, कभी अकाल आता है, कभी पानी ही नहीं रहता, रेलवे से पानी लाना पड़ता है, तो कभी हमारे यहाँ गन्ने का इतना excessive production होता है कि

किसानों को उसे फेंक देना पड़ता है। सर, मुझे बहुत दुःख के साथ यह बोलना पड़ता है कि इस बार, इस सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर शुगर को इम्पोर्ट कर लिया है, जिसके कारण शुगर के रेट्स बहुत गिर गए हैं। फिर शुगर फैक्टरीज़ कैसे चलेंगी? शुगर फैक्टरीज़ ने तो नाबार्ड से फाइनेंस लिया होता है और नाबार्ड जब तक one time settlement नहीं करता, इसमें दिक्कत होगी, ...(समय की घंटी)... सर, सिर्फ एक मिनट .... क्योंकि उसको गवर्नमेंट की गारंटी होती है। इसलिए हम आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इस सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। चाहे शुगर हो, onion हो या कॉटन हो, इसमें market में fluctuation होता है। उनको अच्छी मार्केट मिले, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए।

(4सी/एमसीएम पर जारी)

-SSS/NBR-MCM/4C/6.05

श्रीमती रजनी पाटिल (क्रमागत) : नाबार्ड के माध्यम से डिजिटाइजेशन करके उसको क्रिस्टल क्लियर करने की आवश्यकता है। हैंडलूम सैक्टर है, ट्राइबल है और ट्रेडिशनल आर्टिजंस है, उसके यहां ध्यान देना जरूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो मैंने मुद्दा उठाया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं इतने बड़े पैमाने पर आती हैं, लेकिन उनको backward linkage and forward linkage आजकल नहीं मिल रहा है। नाबार्ड के माध्यम से भी उनको मदद करना जरूरी है। इस तरह से नाबार्ड से बहुत बड़ी आशा लेकर यह जो हम कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो यहां इस देश के गरीब किसानों को, महिलाओं को, हथकरघे पर काम करने वाली महिलाओं को

आर्टिजंस को एक मदद मिल जाएगी, यही अपेक्षा मैं नाबार्ड से रखते हुए अपनी बात को विराम देती हूं, धन्यवाद। (समाप्त)

DR. VIKAS MAHATME (MAHARASHTRA): Mr. Deputy Chairman, Sir, we are all aware that NABARD is a premier institute financing rural India and plays a major role in rural economy. I shall not talk more about NABARD, because everybody knows about it. But, I would like to congratulate the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley ji and Shri Shukla ji, for increasing the capital of NABARD by six times. Previously, the capital was Rs. 5,000 crores and now it is proposed to increase to Rs. 30,000 crores. It is a great jump. It can be more than Rs. 30,000 crores if it is sanctioned from the Reserve Bank of India.

Sir, with this, NABARD will play a major role since its capital adequacy ratio will be better. And, the lending capacity of bank will also become better. It helps in improving rural economy. Youth from rural areas will get more jobs in rural areas. So, migration of youth from rural to urban areas will be less. I think, getting jobs for rural youth is a very important part played by NABARD because of increase in its capital.

I wish to make a suggestion with regard to disbursement of loan. The loan facilities which are provided to farmers are through primary agriculture

co-operative societies. These are working very well in States like Maharashtra and Karnataka, but in some States there has been misappropriation of funds.

There is another organization called Farmer Producer Company. Companies are registered under the Companies Act. So, they will have to submit their income-expenditure and other records annually and there is a strict control over companies. So, the chances of misappropriation of funds by companies are always less. So, I personally feel, the farmer producer companies should get preference over co-operative societies in getting loans for farmers. And, I strongly feel that Farmer Producing Company should be promoted.

Another suggestion is on distribution of loans. Gadchiroli and Nandurbar districts in Maharashtra get less loan disbursement as compared to other districts of Maharashtra. Similarly, some North-Eastern States also get less disbursement of loans from NABARD. I personally feel that priority should be given to those districts and States where loan disbursements earlier were very less. This will help to bring everybody on an equal platform.

Another point I wish to state is that there is a need for increasing irrigation facilities. Whilst NABARD funds flow into rural areas, water will

also flow हमारा एक नारा है, "हर खेत को पानी" and that will be possible only through this Bill. So, I support this Bill. The increase in capital helps NABARD to lend loan for irrigation purpose. We all know that the hon. Water Resources Minister, Shri Nitin Gadkari, will be able to use this money for improving irrigation all over India.

I want to raise another issue. The basic need of farmers -- it has been raised by everybody -- is hand loan. हमेशा किसान कहता है कि मुझे अभी आप पैसा उधार दीजिए, मैं तीन-चार महीने में वापस कर दूंगा, जब फसल आएगी।

(4D/PK-GS पर जारी)

PK-GS/4D/6.10

DR. VIKAS MAHATME (CONTD.): But there is no Government machcinery which can provide loan to a farmer in three, four days. That is why he has to approach the private money lenders. As we all know, once he goes to the private money lenders, he gets trapped into high interest and he never comes out of that. So, I personally feel if we have any project in which money lending is done in three, four days and hand loan will be made available to the farmers, this will save farmers from committing suicides. आज हम एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और इन्वेस्टमेंट की भी बहुत जरूरत है। मैं यदि एक किलो चावल फ्लिपकार्ट

से या अमेज़न से खरीदना चाहता हूं, तो वे लोग मुझे बता सकते हैं कि वह मेरे घर पर कितने बजे, कौन से दिन पहुंचेगा। They can tell us from which store it will be sent, by which road, by which vehicle and who will deliver that at my house. यह सब इसीलिए होता है , क्योंकि उनके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज के लिए गोदाम उनके पास रहता है, चेन मैनेजमेंट है और आई.टी. प्लेटफार्म है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। जब किसान अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, तो उसे पता नहीं होता है कि क्या भाव मिलेगा, वह किस भाव में फसल को बेच पाएगा? इसीलिए हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जाए। इस बिल के पास हो जाने पर नाबार्ड के माध्यम से लोन हम अच्छी तरह से दे पाएंगे, चेन मैनेजमेंट और आई.टी. नेटवर्क भी हम लोगों को दे पाएंगे।... (समय की घंटी)... मैंने एक आई.टी. प्लेटफार्म देखा था, एम -कृषि का देखा था, जो कि बहुत अच्छा था, गवर्नमेंट ने भी उसकी सराहना की है, लेकिन वह अभी तक किसानों तक पहुंचा नहीं है। In short, I would like to say that previously there was a consistency with the Companies Act, 1956. But, now, with this new amendment, the consistency will be with the Companies Act, 2013. So, the farmer producer companies or big farmers will be able to use the facilities of future trading in the SEBI, because farmer producer companies, organisations will be able to participate in Bombay Stock Exchanges or other exchanges more easily because it is in consistency with the Companies Act, 2013.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please conclude.

DR. VIKAS MAHATME: Then, Sir, as regards this Bill, the RBI had a .4 per cent share holding. Since it was the regulatory body as well as the owner of the NABARD, there was a conflict of interest. It is good that the Government has purchased those shares. I personally feel that because of all this हमारा जो बिल है, इसके जरिए से rural economy और strong हो जाएगी, युवा वर्ग को काम मिलेगा, सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा, इसलिए मुझे लगता है कि किसान की आय दुगनी हो सकती है। ...(समय की घंटी).. जो हमारे प्रधान मंत्री जी का नारा है और प्रधान मंत्री का जो सपना है, वह सच हो सकता है, इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Mahatme*ji*. Now, Shri Rajeev Shukla.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं शुक्ला जी को बधाई देता हूं कि वे पहले बिल को पायलेट कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shukla*ji,* you have only five minutes.

श्री राजीव शुक्ल: हम नाबार्ड बिल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी का विज़न था, उन्होंने नाबार्ड को 1981 में शुरू कराया था, किसानों की मदद का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मदद का। नाबार्ड की शुरुआत 100 करोड़ रुपये से हुई थी।

...(व्यवधान)... बाद में वह 5,000 करोड़ रुपये का हुआ और आज इसको सरकार 30,000 करोड़ करने जा रही है, जो कि एक अच्छा कदम है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, किसानों को मदद मिलेगी, कुटीर उद्योग-धंधों को मदद मिलेगी, इसलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं।

सर, जहां तक ट्रांसफर की बात है, आरबीआई का 0.4 परसेंट था, उन सारे शेयर्स को गवर्नमेंट 20 करोड़ में खरीदकर उसको अपने अधीन ले रही है और 51 परसेंट गवर्नमेंट की ईक्विटी होने जा रही है। यह अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इसको संचालित करे, लेकिन इसमें एक चीज़ देखने की बात है। आरबीआई के रेगुलेशन्स होते हैं, आरबीआई की अपनी मॉनिटरिंग होती है और उस हिसाब से वे इस तरह की संस्थाओं को पूरा रेगुलेट करते हैं, जो इस तरह का क्रेडिट देने का काम करते हैं। अब मेरा आपसे आग्रह है कि अब उसको रेगुलेट कौन करेगा, कौन इसको मॉनिटर करेगा? पहले वे आरबीआई की गाइडलाइन्स के तहत होते थे। अब जब रिज़र्व बैंक का आप बिल्कुल इसमें से स्टेक हटा दे रहे हैं, तो आप कैसे इसको मॉनिटर करेंगे, कैसे इसको रेगुलेट करेंगे, इसका मुझे माननीय मंत्री जी से जवाब चाहिए।

(HMS/4E पर जारी)

PB-HMS/4E/6.15

श्री राजीव शुक्ल (क्रमागत) : सर, इस में इंदिरा गांधी का यह मूलभूत concept था कि इस से किसानों, कुटीर धंधों और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े उद्योग-धंधों की मदद हो, लेकिन अब इस में एस0एम0ई0 सेक्टर भी आ रहा है यानी Medium, Small Scale Industries

भी आ रही हैं। इसलिए मंत्रीजी, इस में देखने की बात यह है कि कहीं कॉरपोरेट जगत इस का फायदा न ले ले क्योंकि इस के अंतर्गत सस्ते लोन मिलते हैं। अब आप इस में 10-20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ करने जा रहे हैं, तो कहीं Medium industries इस का लाभ न ले ले और इस का लाभ किसानों और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को जाना चाहिए, वह लाभ उन्हें मिल पाए, यह चीज आप को ensure करनी पड़ेगी क्योंकि किसानों और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लोगों के पास इस के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है। ये बड़े-बड़े nationalized banks, corporate banks, private banks उन्हें लेने नहीं देंगे और न उन की कोई मदद करेंगे। इसलिए देखने की चीज यह है कि किसानों और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से जुड़े लोगों का जो एकमात्र सहारा है, कहीं ऐसा न हो कि उनसे यह सहारा भी छिन जाए और इस में भी वही सेक्टर घुस जाए, जो बाकी private और nationalized banks से लोन ले रहा है। इसलिए आप को वह चीज भी ensure करनी पड़ेगी कि किसानों का हक न मारा जाए क्योंकि इस में Self-help Groups बड़ी मदद लेते हैं। मेरे हिसाब से आप ऐसा करिए कि नाबार्ड का पूरा फोकस Rural Development पर ही रहे। आप को इस चीज को देखना पड़ेगा कि वह कहीं उस से अलग न होने पाए क्योंकि आज पूरे देश में किसानों की हालत बहुत बुरी है। महोदय, चाहे खाद, बीज की बात हो या उन्हें subsidy देने की बात हो, उन सब चीजों में इनका बुरा हाल है।

तीसरी बात, इस में सिंचाई की सुविधा को भी जोड़ा जा सकता है। मेरा एक सुझाव यह भी है कि आप बजाय किसी आई0ए0एस0 ऑफिसर के आर0बी0आई0 के

डिप्टी गवर्नर को इस का चेयरमैन बना दीजिए ताकि इस का regulation और monitoring ठीक से होती रहे। महोदय, मैं आखिरी बात यह कहना चाहूंगा कि नाबार्ड का पैसा नीचे तक पहुंचे, इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं Planning Commission में रहा हूं और देखने में यह आता है कि लाखों करोड़ रुपए इस क्षेत्र को जाता है, लेकिन वह नीचे कहां जाता है, यह पता नहीं चलता। आप गांव में जाकर किसानों से पूछें तो वे बताएंगे कि किसानों को तो कर्ज़ भी नहीं मिल पाता। आप तो खुद गोरखपुर में देखते होंगे कि नीचे तक पैसा नहीं पहुंचता, यह एक बहुत बड़ी समस्या सारी सरकारी योजनाओं और बैंकों की खास तौर से है। ये लोग उन्हें बहुत तंग करते हैं। हालांकि उस में दिल्ली में बैठी सरकार का कोई दोष नहीं है क्योंकि यहां से rural development, rural economy और किसानों व मजदूरों के लिए बाकायदा पैसा भेजा जाता है, लेकिन वह नीचे तक नहीं पहुंचता। आप यह व्यवस्था जिस दिन बना लेंगे कि यह पैसा नीचे तक पहुंच जाए, आप समझ लें कि आप की समस्या का हल हो गया। फिर किसानों के गांव, सोने के गांव हो जाएंगे। महोदय, नीचे तक न नाबार्ड का पैसा पहुंच पाता है, न आप के द्वारा दूसरी योजनाओं में दिया गया पैसा पहुंच पाता है। इसलिए इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप इन्हें 30 हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो आप ensure करिए कि कम-से-कम 80 परसेंट पैसा तो उन तक पहुंचे। आप से छोटे-छोटे किसान और मजदूर लोग मांगते हैं, लेकिन बैंक वाले उन्हें भगा देते हैं। भले ही कोऑपरेटिव बैंकों का फायदा महाराष्ट्र और गुजरात के किसान ले रहे हों, लेकिन यू0पी0, बिहार और इधर के लोगों को बड़ी परेशानी है। इसलिए आप ये जो पैसा दे रहे

हैं, यह एक अच्छा कदम उठा रहे हैं, लेकिन यह नीचे तक पहुंचे, इस के लिए आप जरूर प्रयास करें। हमारा इस पर पूरा समर्थन है और हम इस के साथ हैं, धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI ANIL DESAI (MAHARASHTRA): Sir, I rise to support the National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017.

Sir, the National Bank for Agriculture and Rural Development, that is, NABARD, was basically created for providing and regulating credit and other facilities for the promotion and development of agriculture, small scale industries, cottage and village industries, handicrafts and other rural crafts and allied economic activities in rural areas for promoting integrated rural development and thereby securing prosperity of rural areas.

Sir, this Bill basically aims to amend the NABARD Act, 1981 to increase the authorized capital of the Bank from Rs. 5,000 crores to Rs. 30,000 crores to enable it to meet its objectives.

The other thing is, the RBI is holding 0.4 per cent of the paid-up capital of the Bank which, RBI being a Regulator and Bankers' Bank, was causing conflict of interest in the RBI's role as a banking regulator and shareholder in NABARD. So, that is also being regulated. The Government

is taking over and paying the face value of the transaction which comes to Rs. 20 crores to the RBI, and the entire holding will be of Government.

(Contd. by 4f/SKC)

SKC/4F/6.20

SHRI ANIL DESAI (contd.): This legislation thereby paves the way for taking up rural activities with such a pace that real development as far as the farming community is concerned, and the hon. Prime Minister's prime objective that the farmers' income is doubled by 2022 is realized. I think this legislation would play a pivotal role in reaching the objectives. This Bill allows NABARD to raise the limits of credit. It promotes credit and other facilities to micro enterprises with an investment up to Rs. 25 lakhs. Where hitherto the investment was up to Rs. 20 lakhs, investment limit is being raised from Rs. 5 crore to Rs. 10 crore. Similarly, in the service sector also the investment limits have been increased. That would help the micro, small and medium enterprises to run their activities. This legislation would certainly pave the way for generation of employment in the rural areas. The main service sector for the banks being the rural areas, the local/official language should be the medium of instruction as far as doing business is concerned, since the activities would be specifically in the rural areas and

the focal point of the business would be the farmer. So, in every State having its regional language, which is also termed as the official language of the State, the business needs to be conducted in that language. I hope the hon. Finance Minister would ensure that for conducting business the medium of instruction is the local language of the State.

Similarly, NABARD should ensure presence of one nodal agency of its own in each district of the State to facilitate further lending with the cooperative banks and other financial institutions where the network is such that the lending percolates right up to the beneficiary, that is, the farmer, and to see to it that other well known practices in the rural areas are curtailed, like going to the private moneylender after which his entire future comes under a cloud. So, I think this legislation would pave way for all these activities and rural development in the real spirit would be the order of the day. NABARD, with its set objectives and appropriate measures, would be able to achieve it and by 2022, the hon. Prime Minister's ambitious dream of doubling farmers' income would be achieved through this legislation.

Sir, I support this Bill. Thank you very much.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (ANDHRA PRADESH): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir.

Sir, the NABARD (Amendment) Bill, 2017 envisages an additional inflow of capital of more than Rs. 25,000 crores. I have faithfully perused this Bill and I understand that it is only an enabling provision; it is not a mandatory provision. I hope the Minister of State for Finance, sitting here, would come back to this House with an Appropriation Bill, starting with the present Budget itself, to the extent of more than Rs. 25,000 crores, even though it is inadequate to meet the agrarian crisis that plagues India. So, let me repeat, it is an enabling provision. There has to be an appropriation to the extent of an additional Rs. 25,000 crores, as suggested in this Bill.

Sir, I have four concerns and three suggestions that I wish to make in this regard. I draw your kind attention to the National Sample Survey Organization which has reported the situation. It has been reported by the National Sample Survey Organization that institutional credit has consistently been coming down since 1991 till 2013.

(CONTD. BY HK/4G)

HK/4G/6.25

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): In fact, in 1991, the institutional credit was approximately 69.4 per cent whereas it has come down in 2013 to 56 per cent. A fall of approximately 15 per cent is really sizable and we are all concerned with that. Alternatively, on the other hand, the non-institutional credit, that is, private moneylender's credit, which was 30.6 per cent in 1991, has gone up to 44 per cent. The increase in non-institutional funding is really significant and alarming also. Therefore, I request the Government of India to take cognizance of it and increase the institutional funding to the farming sector. Coming to Andhra Pradesh, I draw your kind attention to the fact that there are approximately 7.56 lakh pure tenant farmers and 24.37 lakh are owner-cum-tenant household farmers. Out of total suicides by farmers, 50 per cent of the farmers who are committing suicides are only tenant farmers. Therefore, you will have to address the problem of tenant farmers also, not owner farmers alone. My suggestion in this regard is that you will have to increase the institutional funding for the farming sector to meet the agrarian crisis. Sir, my second point is related to increasing indebtedness of farmers. This is what my observation is. The same National Sample Survey Organisation reported the worsening situation of

indebtedness of farmers in India. Sir, the indebted farm households in India, as of today, are about 51.9 per cent and the indebted households in Andhra Pradesh are 93 per cent, whereas the national average is only 51.9 per cent. In Andhra Pradesh, indebted farm households are to the extent of 93 per cent which is very alarming. Average outstanding debt of a cultivator household in Andhra Pradesh is Rs.1,23,000 which is really alarming. Why is this indebtedness? This indebtedness is on account of non-availability of institutional credit and these farmers are borrowing from private financers who are charging exorbitant rates of interest to the extent of 24 per cent to 28 per cent or 30 per cent. This situation has to be addressed. I request the hon. Minister of State of Finance to address this problem and make the credit available to the farmers. Sir, the third important point is regarding complementing credit with knowledge dissemination. Sir, in fact, NABARD has decided to lend -- I hope, this is what the information I have collected -- not only to the farmers through banks but also to the research organizations and also to the farmers who are conducting the research. This has to be complimented and it is a good thing. You will have to increase the funding to the research organizations and to the farmers conducting the research. My last point is related to high interest rate. The system which is being

followed by the bankers for non-agricultural sector is Marginal Cost of Funds based Lending Rate, which is called MCLR. The MCLR adopted by the RBI is such a system which forces lenders to readjust their lending rates monthly based on the repo rate changes and certain other parameters. I hope NABARD also would implement the same and the Government of India need to consider this. I hope that the Ministry of Finance would address these problems. I am concluding and supporting this Bill. Thank you.

(Ends)

(Followed by KSK/4h)

KSK/KLG/6.30/4H

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA): Respected Deputy Chairman, Sir, I salute the grand great memory of Indira Gandhiji, whose 100th birth anniversary was celebrated on November 19. She was the Prime Minister who conceived and enacted this law in 1981 and this led to establishment of the National Bank for Agriculture and Rural Development, with Mumbai as its headquarters, in 1982. From then on, the saga of the National Bank for Agriculture and Rural Development Bank is the saga of success and it has become the household name among the agricultural, rural and co-operative credit agencies. Then, in 2011, during the UPA

Government, we had decided to infuse Rs.30,000 crores into NABARD for strengthening its financial and financing capacities.

Sir, I appreciate the present Government for taking up and initiating the increasing of the paid-up capital from Rs.5,000 crores to Rs.30,000 crores. But times are changing. Transformation is wide. NABARD is being assigned very many and a variety of tasks. Basically, it has the mandate of re-financing, but it is looking after the health and capacity of the regional rural banks. It is also a caretaker of co-operative credit structure and credit revival. Keeping these factors in mind, with the additional responsibilities of financing irrigation and housing projects, we need to have a special focus to save NABARD in its capacity. If we study the health and capacity of the China National Rural Bank, it is one of the world's largest banks having the capacity to cater to the budgetary needs of China, this NABARD is not growing on par with that expansion. However, it is the successful story of NABARD, which has great impact on State Governments' rural development-oriented projects.

Sir, I have special pleasure and my appreciation is on record to the present Government for including handlooms in the financing responsibility of the NABARD. With the times' transition, you are rightly changing the

nomenclature from small-scale industries, cottage and village industries to micro enterprises, small enterprises and medium enterprises, cottage and village industries and handlooms. I welcome it. We did not have the backup support. Being the son of the weaving community, being the son of the weaving occupation, being the son of the weaving profession, I take extraordinary pleasure for strengthening us, empowering us. Our handloom sector will definitely feel safe with the re-financing support of this NABARD through this enactment.

At the same time, I have my apprehension and I re-emphasise that the micro enterprises, the small enterprises, the medium enterprises shall invariably be under the Agricultural and Rural Development and rural enterprise orientation only. Otherwise, it will be going into the hands of the corporates, those who have the urban and semi-urban orientations.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

(Followed by 4J – GSP))

GSP-AKG/4J/6.35

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Keeping in view the burden of NABARD to look after 140 Regional Rural Banks and to cater to the needs of cooperative sector, I have one request. Yes, all the States are looking

towards NABARD for its support. Likewise, my State, Telangana, is also looking towards NABARD for support.

I request the Union Government and the Union Finance Ministry to encourage NABARD to finance, as promised, to the cleaning of Musi river, which also will give safe water to Hyderabad and its surroundings. Besides that, you are going to finance irrigation projects to the tune of 77,000 crores of rupees. In that, 11 projects are from Telangana, for which NABARD has assured to give 7,000 crores of rupees. Apart from expeditious decisions, I expect that several projects which are being contemplated by NABARD shall be agriculture and rural development-oriented only. With this suggestion and advice, I appreciate, welcome and support this Bill. Thank you very much. (Ends)

MR. DEPTY CHAIRMAN: Thank you. Now, hon. Minister, Shri Shiv Pratap Shukla.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला) : माननीय उपसभापति जी, डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं। उन्होंने इस विषय के प्रवर्तन के समय इस बात को कहा था कि सहकारिता के क्षेत्र में नाबार्ड से भी धन देना चाहिए। उनके चर्चा शुरू करने के बाद नारायण लाल पंचारिया जी, नीरज शेखर जी, एन. गोकुलकृष्णन जी, मनीष गुप्ता जी, प्रसन्न आचार्य जी, राम नाथ ठाकुर जी, तपन कुमार

सेन जी, वीर सिंह जी, राम कुमार कश्यप जी, डी. राजा जी, श्रीमती रजनी पाटिल जी, डा. विकास महात्मे जी, राजीव शुक्ल जी, अनिल देसाई जी, विजयसाई रेड्डी जी और आनंद भास्कर रापोलू जी ...

श्री उपसभापति : सब लोगों ने इसे support किया है, और क्या चाहिए?

श्री शिव प्रताप शुक्ला : सभी लोगों ने इस बिल का support किया है और साथ-साथ मुझे भी support किया है, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ बिल रख रहा हूँ।

श्री उपसभापति : हमारा इसको पूरा support है।

श्री नीरज शेखर : मेरा सबसे ज्यादा support है।

श्री जयराम रमेश : सर, वे back bench से front bench पर आ गए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. That is destiny. Back bencher front bench पर आएँगे और front bencher back bencher भी हो जाएँगे।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर) : लेकिन वे वहीं के वहीं रहेंगे।

श्री उपसभापति : इधर से उधर भी जाएँगे, उधर से इधर भी आएँगे।

श्री प्रकाश जावडेकर : वे वहीं के वहीं रहेंगे।

श्री उपसभापति : दोनों हो सकता है। इधर से उधर और उधर से इधर हो सकता है।

श्री शिव प्रताप शुक्ला : सर, नीरज शेखर जी ने अपनी बात रखी थी, मैं उसका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक उन्होंने NPA के संदर्भ में जो कहा था कि नाबार्ड का NPA कितना है, तो चूँकि नाबार्ड बैंकों को ही पैसा देकर विभिन्न माध्यमों से, चाहे किसान हो, चाहे

MSME हो, उनको ही प्रोन्नत करता है, इस नाते उसको पैसा बैंक से लेना है। ऐसी स्थिति में उसके NPA का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

श्री नीरज शेखर : क्या बैंकों से नाबार्ड के पास सारा पैसा वापस आ जाता है?

श्री शिव प्रताप शुक्ला : हाँ, धीरे-धीरे आ जाता है। अब तो इसी नाते और भी काम कर दिया गया है।

श्री नीरज शेखर : इसका मतलब है कि किसान पैसा रूरल बैंक को देता होगा, तो उससे नाबार्ड को वापस आ जाता होगा। किसान पैसा देता होगा, तभी तो वापस आता होगा!

श्री शिव प्रताप शुक्ला : किसान की तरफदारी के लिए आप जो कह रहे हैं, मैं उसके साथ हूँ।

श्री नीरज शेखर : धन्यवाद।

श्री शिव प्रताप शुक्ला : उपसभापति जी, बात इसकी आ रही थी कि कोऑपरेटिव सेक्टर को कितना धन दिया गया है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर को LTRCF में 15 हजार करोड़ रुपए और STRCF में 45 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।

(4के/एससीएच पर जारी)

SCH-SK/6.40/4K

श्री शिव प्रताप शुक्ला (क्रमागत) : और प्रधान मंत्री जी ने additional 20,000 करोड़ रुपये देने के लिए भी एनाउंस किया था। प्रधान मंत्री जी बहुत उचित प्रकार से अपनी नीतियों को लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं।

एक शंका यह भी की गई कि यह कैसे होगा? इसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि 2022 तक हम किसान की आय निश्चित रूप से दोगुनी कर देंगे, इसलिए आप यह विश्वास रखिए कि 2022 की स्थिति तक वर्तमान सरकार, जो आगे भी चलती ही रहेगी ही, वह किसान की आय अवश्य दोगुनी करेगी। इसमें शंका की कोई बात नहीं है।...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : यह कैसे होगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ला : अभी पहले आप इस बिल पर तो बहस कर लीजिए, उसके बाद यह भी बताएंगे कि वह कैसे होगा।

नाबार्ड में आरबीआई के तीन डायरेक्टर्स हैं। श्री राजीव शुक्ल जी ने एक बात कही थी, जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। उनकी आशंका यह थी कि अभी तक तो RBI ही इसकी regulatory authority थी, लेकिन कल इसका क्या होगा? इस संबंध में मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज भी नाबार्ड की regulatory authority RBI ही है, उसको हटाया नहीं गया है। आगे भी वह उसी की देखरेख या संरक्षण में चलता रहेगा। मान्यवर, अभी RIDF के अंतर्गत चर्चा हुई थी, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अधिक राशि उपलब्ध करवा रही है और इस बात की चर्चा कई राज्य सरकारों ने की है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि आन्ध्र प्रदेश को और अधिक राशि दी जाए। केन्द्र सरकार ने 2014-15 में राज्य सरकारों को 19,666 करोड़ रुपये, 2015-16 में 23,510 करोड़ रुपये और 2016-17 में 25,600 करोड़ रुपये इसके तहत उपलब्ध करवाए हैं। जब मनीष गुप्ता साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने

इस बात का विशेष उल्लेख किया था। केन्द्र सरकार ने हमेशा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध करवाने का काम किया है।

कई माननीय सदस्यों ने इस आशंका को व्यक्त किया कि नाबार्ड की कैपिटल को कहीं private shareholders को देने की मंशा तो नहीं है। आप इस बात से आश्वस्त रहिए, इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है, सरकार ने इसको अपने पास ही रखा है। नाबार्ड जैसा था, वैसा ही रहेगा, केवल किसानों के हित को देखते हुए, एमएसएमई के हित को देखते हुए, सरकार ने उसकी शेयर राशि को बढ़ाया है। एक बात और हो रही थी कि 30,000 करोड़ रुपये की राशि अंतिम होगी? मैं बताना चाहूंगा कि 30,000 करोड़ रुपये की राशि अंतिम नहीं है। RBI से इस विषय पर फिर से बातचीत करके यह राशि 50,000 करोड़ या उससे अधिक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यह राशि उतनी ही रहेगी।

महोदय, जो यह बिल लाया गया है, उसका स्वाभाविक रूप से सभी लोगों ने समर्थन किया है। मैं समझता हूं कि यह बिल किसानों के हित में है, एमएसएमई के हित में है, साथ ही साथ राज्यों के हित में भी है। जैसा कि पंचारिया जी पूछ रहे थे, चाहे सिंचाई की परियोजना हों अथवा अन्य परियोजनाएं हों, वह इन सब कार्यों में कहीं न कहीं मदद करने का कार्य ही करेगी।

एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों से इसके लिए आग्रह करता हूं। जो छोटी-छोटी शंकाएं थी, उनको दूर करने का मैंने प्रयत्न किया है, फिर आप लोगों ने तो बहुत ही

विद्वान वित्त मंत्री पाए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे चलकर सब कुछ और भी ठीक हो जाएगा।...(व्यवधान)...

श्री राम नाथ ठाकुर : वित्त मंत्री जी, बिहार में जो 164 योजनाएं लम्बित हैं, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री शिव प्रताप शुक्ला : मैंने अलग से किसी राज्य के बारे में नहीं कहा है। मैंने सिर्फ यह बताया है कि राज्यों को इतनी-इतनी राशि दी जाती है, उसी में बिहार भी आता है।

श्री उपसभापति : मंत्री जी, अगर आपके पास डिटेल्स नहीं हैं, तो आप उनको लिख कर भेज दीजिएगा। अभी आप बैठ जाइए।

The question is:

"That the Bill further to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

(Followed by YSR/4L)

YSR-RPM/6.45/4L

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one Amendment (No.1) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, the Amendment is not moved.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there are five. Amendments Nos. (2-4) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, these Amendments are not moved.

Amendment Nos.7 and 8 are by Shri K.K. Ragesh. He is moving the Amendments.

CLAUSE 5 – AMENDMENT OF SECTION 4

SHRI K.K RAGESH (KERALA): Sir, I move:

(7) That at page 2, ***for*** lines 17 to 21, the following be ***substituted,*** namely:-

"Provided that the Central Government may, in consultation with the Reserve Bank and by notification, increase the said capital to thirty thousand crore rupees:

Provided further that the Central Government may, in consultation with the Reserve Bank and by notification, further increase the said capital to such amount as it may deem necessary from time to time:

Provided also that the combined shareholding of the Central Government and the Reserve Bank shall not at any time be less than one hundred per cent of the total subscribed capital".

(1)That at page 2, lines 22 to 31, be ***deleted.***

Sir, I know that the RBI is the regulator. But, at the same time, it frames credit policies and that ensures that credit goes to the priority sectors, especially agriculture cooperatives, SMEs, etc. I feel that there should be proper liaison between NABARD and the Government of India and the RBI. That is why I am moving these amendments. Also, why is it 51 per

cent? Why shouldn't it be 100 per cent? That should be 100 per cent on the part of the Central Government.

The questions were put and the motions were negatived.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 8, there is one Amendment (No.5) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, the Amendment is not moved.

Clause 8 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 9, there is one Amendment (No.6) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, the Amendment is not moved.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 to 13 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 1, there is one Amendment (No.9) by the Minister, Shri Shiv Pratap Shukla.

SHRI SHIV PRATAP SHUKLA: Sir, I move:

(9) That at page 1, line 4, ***for*** the figure "2017", the figure "2018" be ***substituted***.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Clause 1, as amended, to vote.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHIV PRATAP SHUKLA: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

(**Ends**)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Two Bills have been passed. Today, we passed two Bills. Earlier also we passed two Bills. It was very constructive. ...(Interruptions)...

MESSAGE FROM LOK SABHA

THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMENDMENT) BILL, 2018

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2018, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 2nd January, 2018."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table. (Ends)

(Followed by VKK/3F)

-YSR/VKK-PSV/4M/6.50

(THE VICE-CHAIRMAN, SHRI BHUBANESWAR KALITA, in the Chair)

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 2nd of January, 2018 has allotted time for Government Legislative Business, as follows:-

BUSINESS	TIME ALLOTTED
1. Consideration and agreeing to the Amendments made by Lok Sabha in the Constitution (One Hundred and Twenty-Third Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha, as reported by the Select Committee of Rajya Sabha and as passed by Rajya Sabha with amendments.	**Three hours** ***(To be discussed together)***
(2) Further consideration and passing of the National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha.	
(3) Consideration and passing of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of Rajya Sabha.	**Three Hours**

(4) Consideration and passing of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha. **Four Hours**

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Special Mentions. Shri Tiruchi Siva.

SPECIAL MENTIONS – CONTD.

DEMAND FOR EXEMPTING COST OF DRILLING OF BOREWELLS FOR IRRIGATION PURPOSES FROM PURVIEW OF G.S.T.

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Sir, the most common source of water supply for the Indian agriculture sector are borewells, especially in the areas where the rainfalls are scanty. Groundwater in India provides for largest irrigation source which is 61.6 per cent. Hence, it is important that the cost of drilling borewells must be considered for exemption from the GST framework. It is believed that there are about 10,000 rigs that operate within the country, which provide services to the agriculture sector and were exempted from service tax earlier. The cost of each vehicle is about Rs.1 crore and requires 5-6 workers. It is very difficult for the rig owners to predict the hours of work because of the seasonal nature of agriculture and the cost of rigging is calculated according to per feet of drilling done. In such a

scenario, it will be very difficult for the rig owners to cover various responsibilities of obtaining certificates of registration amongst other things for GST filing. Most of the rigs use diesel which is kept out of the GST framework. If GST levied on rigs, it will increase the cost for the farmers which will be an added burden for them.

Sir, I urge the Government to exempt the drilling of borewells for water supply for agriculture from GST in the interest of the farmers in the country who rely solely on borewell for agriculture water supply. It will immensely reduce their burden as additional costs will be avoided. Thank you.

(Ends)

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Shri Tiruchi Siva.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by Shri Tiruchi Siva.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by Shri Tiruchi Siva.

SHRI K. SOMAPRASAD (KERALA): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by Shri Tiruchi Siva.

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विशेष उल्लेख से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the Special Mention made by Shri Tiruchi Siva. (Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Dr. V. Maitreyan; not here. Shri Sanjay Raut; not here.

The House stands adjourned till 1100 hours on Wednesday, the 3rd January, 2018.

The House then adjourned at fifty-four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 3rd January, 2018.